सनरेफ भारत – हरित आवास पर आउटरीच कार्यक्रम

रा.आ.बैंक, एएफडी एवं ईयू द्वारा हरित किफायती आवास हेतु जागरूकता लाने के संबंध में

बेंगलुरु, 28 फरवरी, 2022

दिल्ली, मुंबई एवं कोलकाता में कार्यक्रमों के सफल आयोजन के पश्चात; सनरेफ (प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग एवं ऊर्जा दक्ष आवास वित्त) हाउसिंग इंडिया कार्यक्रम ने बेंगलुरु, कर्नाटक में अपना तीसरा क्षेत्रीय प्रचार कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें हरित किफायती आवास की आवश्यकता को रेखांकित किया गया एवं इस कार्यक्रम में मौजूद आवास बाजार के 80 प्रमुख हितधारकों को हरित किफायती आवास की प्रमुख विशेषताएं प्रदर्शित की गई।

भारत में हरित किफायती आवास परियोजनाओं को गति प्रदान करने के उद्देश्य से, सनरेफ हाउसिंग इंडिया कार्यक्रम को जुलाई 2017 में राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक) के साथ साझेदारी में फ्रांसीसी विकास एजेंसी फ्रांस विकास एजेंसी (फ्रांस विकास एजेंसी, एएफडी) द्वारा आरंभ किया गया था। यह परियोजना यूरोपीय संघ (ईयू) द्वारा सह-वित्त पोषित है। विशेष रूप से, इसमें एएफडी से €100 मिलियन की एक नवोन्मेषी ऋण व्यवस्था शामिल है जो बैंकों, आवास वित्त कंपनियों (आ.वि.कं.) को हरित तथा किफायती आवास परियोजनाओं एवं इससे संबद्ध निवेशों के निधियन हेतु सक्षम बनाती है। आवास वित्त कंपनियों को प्रदान किये जाने वाले ऋण कम ब्याज दर पर उपलब्ध कराने तथा कार्यक्रम के लिए प्रोत्साहन एवं क्षमता निर्माण के उद्देश्य से ईयू द्वारा €9 मिलियन निवेश अनुदान एवं €3 मिलियन तकनीकी सहायता अनुदान, वित्तपोषण को सुलभ बनाने के लक्ष्य के साथ प्रदान किया गया है जो कि इस कार्यक्रम को एक अंकाक्षी एवं नवोन्मेषी कार्यक्रम बनाता है।

बेंगलुरु में आयोजित इस कार्यक्रम में कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश राज्यों के बैंकों, आवास वित्त कंपनियों, रियल एस्टेट विकासकों, सरकारी एजेंसियों, हरित निर्माण विशेषज्ञ, आर्किटेक्ट तथा हरित सामग्री उत्पादकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

कार्यक्रम में वक्ताओं के रूप में एएफडी, भारत में यूरोपीय संघ का प्रतिनिधिमंडल, राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक), इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (आईजीबीसी) एवं ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट (गृह) के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

रा.आ.बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री. वी. वैदीश्वरन ने अपने सम्बोधन में कहा, "*बेंगलुरू शहर में आयोजित सनरेफ इंडिया कार्यक्रम के इस तीसरे क्षेत्रीय प्रचार कार्यक्रम का आयोजन करना बहुत उपयुक्त है, जिसमें तीव्र जनसंख्या वृद्धि एवं तेजी से शहरीकरण देखा गया है। भारत में आवासीय बंधक बाजार के आकार को देखते हुए यह महसूस किया गया है कि यह समय आवासीय निर्माण क्षेत्र में बनाए जा रहे नए पारिस्थितिकी तंत्र को परिवर्तित एवं अनुकूलित करने हेतु उपयुक्त है।*

सनरेफ इंडिया हाउसिंग कार्यक्रम ने अब तक 4,400 परिवारों को पुनर्वित्त प्रदान किया है, जिनमें से आधे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं। हरित किफायती आवास को बढ़ाने के लिए रा.आ.बैंक के प्रयास जलवायु परिवर्तन का समर्थन करने हेतु भारत सरकार की प्राथमिकता के अनुरूप ही हैं।

यूरोपीय संघ एवं आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार स्मार्ट एवं सतत शहरीकरण पर साझेदारी के तहत मिलकर सहयोग कर रहे हैं। कार्बन उत्सर्जन को कम करने और सततता को प्राप्त करने में हरित भवन के महत्व के संबंध में बात करते हुए, **सुश्री कमिला क्रिस्टेंसन राय, काउंसलर, भारत में यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल** ने कहा,*"यूरोपीय संघ एवं भारत दोनों ही ग्रीन ट्रांजिशन पर मिलकर कार्य कर रहे हैं, जिसमें आवास क्षेत्र में नवाचार एक महत्वपूर्ण स्तंभ है।* हम सहर्ष सनरेफ इंडिया के साथ साझेदारी कर रहे हैं, जो देश में हरित पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में सहायता कर रहा है। हम मानते हैं कि स्थानीय संदर्भ में उपयुक्त हरित उपकरण एवं समाधान पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा कुशल और साथ ही किफायती आवास क्षेत्र में सहायता प्रदान कर सकते हैं"।

सुश्री इसाउरे डे बेलेविल, पोर्टफोलियो प्रबंधक, एनर्जी एंड क्लाइमेट फाइनेंस एएफडी, ने कहा कि, "*एक प्रमुख उत्सर्जक क्षेत्र, आवास निर्माण बड़े पैमाने पर ऊर्जा का उपभोग करता है। देश में आवास की कमी है, लेकिन चल रहे आवास निर्माण का जलवायु परिवर्तन सहित पर्यावरण पर दीर्घकालिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भारत में केवल 1% भवन हरित भवन मानदंडों के अनुरूप हैं। इस प्रकार, इस क्षेत्र में हरित दृष्टिकोण को अपनाने संबंधी संभावनाएं अपार हैं।"* एएफडी जागरूकता पैदा करने एवं देश में हरित किफायती आवास क्षेत्र को बढ़ाने हेतु रा.आ.बैंक को सहर्ष सहयोग प्रदान कर रहा है।

राजीव गांधी हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता श्री आर मालाथेशा ने कहा कि, *कम ऊर्जा की खपत करने वाले हरित भवनों का निर्माण महत्वपूर्ण है। यह प्राकृतिक संसाधनों की कमी को नियंत्रित करने एवं पर्यावरण की सततता को बनाए रखने में सहायता करेगा। सनरेफ इंडिया कार्यक्रम रियल एस्टेट निर्माण के नकारात्मक प्रभावों को नियंत्रित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है जो कि हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।*

दक्षिण भारत के बेंगलुरु एवं अन्य महानगरों में पिछले दशकों में ग्रीन-रेटेड आवासीय भवनों में वृद्धि देखी गई है। इसी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, यह कार्यक्रम शहर में आयोजित किया गया था तथा इस कार्यक्रम का उद्देश्य हरित किफायती आवास के महत्व एवं संभावनाओं के संबंध में जागरूकता बढ़ाना था। प्रतिभागियों को हरित प्रमाणपत्र प्रणाली के साथ-साथ उदाहरणात्मक मामलों पर अध्ययन प्रस्तुत किए गए।

श्री विशाल गोयल, महाप्रबंधक, रा.आ.बैंक ने कहा कि "*लाखों आवासीय भवन हैं जो ऊर्जा एवं जल दक्षता बढ़ाने हेतु काफी अवसर प्रदान करते हैं, तथा समग्र रखरखाव लागत को और कम करते हैं। सनरेफ एक ऐसा मंच है जो हरित आवास क्षेत्र से संबंधित वरिष्ठ हितधारकों को एक मंच पर एक साथ लाता है ताकि विचारों का आदान-प्रदान किया जा सके एवं लक्ष्य के रूप में देश में हरित आवास के विकास की दिशा में कार्य किया जा सके"।*

श्री पीयूष पांडे, सहायक महाप्रबंधक-क्षेत्रीय कार्यालय (रा.आ.बैंक) के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।

यूरोपीय संघ के बारे में

यूरोपीय संघ, जिसमें 27 देश शामिल हैं, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और चीन और भारत के बाद तीसरी सबसे बड़ी आबादी है। हालांकि समृद्ध रूप से विविध, यूरोपीय संघ में शामिल देश (इसके 'सदस्य राज्य') सभी

समान बुनियादी मूल्यों: शांति, लोकतंत्र, कानून पर आधारित शासन एवं मानवाधिकारों के सम्मान हेतु प्रतिबद्ध हैं। यूरोपीय संघ ने सीमा-मुक्त एकल बाजार एवं एकल मुद्रा (यूरो) की स्थापना करके जिसे 19 सदस्य देशों द्वारा अपनाया गया है, व्यापार तथा रोजगार को महत्वपूर्ण बढ़ावा दिया है।

यूरोपीय संघ-भारत संबंध: 2022 में यूरोपीय संघ एवं भारत ने राजनयिक गठबंधन के 60 वर्ष पूरे किये है। 60 वर्षों में, यूरोपीय संघ एवं भारत ने गरीबी को कम करने, आपदाओं को रोकने, व्यापार का विस्तार करने, वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं को सुरक्षित करने, दुनिया भर में सुरक्षा बढ़ाने तथा ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि एवं पारस्परिक हित के कई अन्य क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु मिलकर कार्य किया है।

एएफडी के बारे में

एएफडी एक समावेशी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान है एवं फ्रांस की विकास नीति का प्रमुख सहयोगी है। यह उन परियोजनाओं हेतु प्रतिबद्धताओं को शामिल करता है जो वास्तव में विकासशील एवं उभरते देशों तथा फ्रांसीसी विदेशी क्षेत्रों में लोगों के दैनिक जीवन में सुधार करता हैं। एएफडी कई क्षेत्रों - ऊर्जा, स्वास्थ्य, जैव विविधता, पानी, डिजिटल तकनीक, प्रशिक्षण में कार्य करता है - एवं सुरक्षित, अधिक न्यायसंगत एवं अधिक सतत दुनिया: एक साधारण दुनिया हेतु परिवर्तन का समर्थन करता है। इसके कार्य पूरी तरह से सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के अनुरूप है। अधिक जानकारी हेतु एएफडी की: https://www.afd.fr/en वेबसाइट का संदर्भ लें। 5 एजेंसियों के अपने नेटवर्क के माध्यम से, एएफडी 115 देशों में कार्य करता है तथा वर्तमान में 4,000 से अधिक विकास परियोजनाओं की सहायता कर रहा है। 2018 में, एएफडी ने इन परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु 11.4 बिलियन यूरो निर्धारित किए।

सनरेफ के बारे में

सनरेफ परिवर्तित हो रहे देशों में आर्थिक कार्यों की आवश्यकता के अनुरूप "हरित" वित्त के उद्भव को बढ़ावा देने हेतु एएफडी द्वारा विकसित एक नवीन उपकरण है। इसका उद्देश्य स्थानीय वित्तीय संस्थानों को जलवायु परिवर्तन के संबंध में कदम उठाने से संबंधित सहायता करना है। सनरेफ हरित ऊर्जा तक पहुंच को सुगम बनाने एवं प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता तथा तकनीकी सहायता के माध्यम से वित्तीय कार्यों की प्रथाओं को विकसित करने में सहायता करता है। कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था का विकास सुनिश्चित करना एवं आर्थिक कार्यों को इस परिवर्तन के अनुकूल होने देना इसका अंतिम लक्ष्य है। अधिक जानकारी हेतु सनरेफ की: https://www.sunref.org/en/ वेबसाइट का संदर्भ लें।

रा.आ.बैंक के बारे में

राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक) की स्थापना 9 जुलाई 1988 को राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के तहत की गई थी। राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना स्थानीय और क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर आवास वित्त संस्थानों के संवर्धन हेतु एक प्रमुख एजेंसी के तौर पर कार्य संचलान तथा ऐसे संस्थानों को वित्तीय एवं उनसे संबंधित विषयों के लिए अन्य सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई है। अधिक जानकारी हेतु रा.आ.बैंक की: https://nhb.org.in/ वेबसाइट का संदर्भ लें।